

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1588/2015

महावीर प्रसाद यादव

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), झुंझुनू।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड—तृतीय के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने सेवाएं दिनांक 07.09.1982 को जोईन की। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी रूप से हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.12.1988 के द्वारा नियुक्ति दिनांक से स्थाई किया गया, जिसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति, बुहाना के द्वारा आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक 07.09.1982 मानते हुए 9 वर्ष पश्चात दिनांक 07.09.1991 से प्रदान किया गया है। अपीलार्थी को उसके पश्चात 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 07.09.2000 के स्थान पर दिनांक 01.08.2002 को गलत रूप से प्रदान किया गया, जिसमें प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.08.1984 गलत दर्शायी गई। जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 07.09.1982 को हुई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रीनिंग की दिनांक से नियमित मानी गई, जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति उससे पूर्व हुई थी। अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से प्राप्त करने अधिकारी था, जबकि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी नियमित नियुक्ति की दिनांक 01.08.1984 मानते हुए दिया गया है, जो गलत है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :-

"It is therefore most humbly prayed that this appeal may kindly be allowed and call for the record and examining the same the impugned orders dated 16.9.2008 (Annex-4) and order dated 7.6.2012 (Annex-5) may kindly be declared null and void and further be quashed and set aside and the respondents directed to count his services from the date of initial appointment i.e. 7.9.1982 for the purpose of selection grade as well as retiral benefits and 9% interest be also awarded on arrears which admissible to the appellant in consequence of the entitlement.

Any other order, which this Hon'ble Court deem just and proper may kindly be passed in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरण में यह मत प्रतिपादित किया है कि चयनित वेतनमान के लिये सेवा की गणना नियमित नियुक्ति तिथि से ही की जावेगी। इस प्रकार अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राज्य सरकार के आदेशानुसार चयनित वेतनमान नियमित नियुक्ति तिथि से ही देय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3620/2009 निर्णय दिनांक 08.05.2009 द्वारा यह स्पष्ट रूप से एसीपी स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देशो जारी किये गये जिसके सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र No.F.16(2)FD(Rules)/98 Jaipur Dated 20 Aug 2010 जारी किया गया है। जिसके अनुसार किसी भी कार्मिक को उसकी नियमित नियुक्ति तिथि से ही एसीपी का लाभ दिया जाना है जिसके सन्दर्भ में याचिकाकर्ता को तृतीय एसीपी जिला स्थापन समिति द्वारा चयनित दिनांक से स्वीकृत की गई। राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र No.F.16(2)FD(Rules)/98 Jaipur Dated 20 Aug 2010 की अनुपालना में ही निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित कार्मिको को उनकी नियमित नियुक्ति तिथि से ही एसीपी के लाभ स्वीकृत किये जाते है जिसके अनुसार ही कार्मिको को एसीपी जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग/चयनित तिथि के अनुसार स्वीकृत की जाती है।
3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जो आदेश दिनांक 07.09.1982 के द्वारा हुई थी वह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी थी। इस प्रकार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया से नहीं की गयी थी। अपीलार्थी की सेवा को

नियमित किये जाने के सम्बन्ध में स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक की गई और अपीलार्थी को स्क्रिनिंग के बाद नियमित किया जाना प्रत्यर्थी विभाग ने बताया है।

5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिंदुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
 (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
 (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
 (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
 (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। अतः अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 01.08.1984 से नियमित मानी गयी है, उसी दिनांक से अपीलार्थी चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उससे पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लिये नहीं जुडवा सकता है।
7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)